



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 16, 1985/आश्विन 24, 1907

No. 204]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 16, 1985/ASVINA 24, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate Faging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वाणिज्य सत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

1 2 3 4

सार्वजनिक सूचना सं० 12-आई टी सी (पी एन)/85—88

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 1985

विषय—अप्रैल 1985—मार्च 1988 के लिये आयात-निर्यात नीति।

फा० सं० आई टी सी-3/7/85 --वाणिज्य सत्रालय की सार्वजनिक
सूचना सं० 1-आई टी सी (पी एन)/85—88, दिनांक 12 अप्रैल, 1985
के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल 1985—मार्च 1988 के लिये यथा सशोधित
आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2 नीति में निम्नलिखित सशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर
किये गये समझे जायेंगे :—

क्रम	आयात- सं० निर्यात नीति	सदर्थ	संशोधन
	1985—88 (खण्ड-I की) पृष्ठ सं०		
1	38	अध्याय 7 पैरा 127(5)	इस उप-पैरे के स्थान पर निम्न- लिखित उप-पैरा रखा जायेगा — (5) तेल और प्राकृतिक गैस

आयोग, आयल इण्डिया लि० और
भारतीय गैस प्राधिकरण लि० की
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
मन्त्रालय के अधीन तेल उपयोग में
देशीयकरण सम्बन्धी प्राधिकृत
समिति द्वारा अपेक्षित विदेशी मुद्रा
के रिलीज और स्वीकृति के बाद
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की
(परन्तु किसी भी प्रकार से वर्णित
उपभोक्ता माल को छोड़कर) आयात
करने के लिये खुले सामान्य लाइसेंस
के अन्तर्गत अनुमति दी गई है।
इस सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत करने
पर सीमाशुल्क प्राधिकारी खुले
सामान्य लाइसेंस के अधीन निर्यात
की स्वीकृति देगे। मर्यादित-माल
तकनीकी विकास या हलैकट्रानिकल
विभाग से वर्णित श्रुति-करण से स्वीकृति
प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।”

2 39 अध्याय 7 (7) इस उप-पैरा की सातवीं और
पैरा 127(7) आठवीं पंक्तियों में प्रदर्शित शब्द,

1	2	3	4	1	2	3	4
			“महानिदेशालय तकनीकी विकास/इलेक्ट्रॉनिकी विभाग से देशीय दृष्टि से निकासी” के स्थान पर “पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन तेल उद्योग में देशीयकरण सम्बन्धी प्राधिकृत समिति से स्वीकृति” शब्द रखे जायेंगे।				India Limited and Gas Authority of India Limited, have been allowed to import its requirements (but not consumer-goods, howsoever described) under the Open General Licence, after requisite release of foreign exchange and clearance by the Empowered Committee on Indigenisation in the Oil Industry under the Ministry of Petroleum and Natural Gas. The Customs Authority will allow clearance under OGL on production of evidence to this effect. No indigenous clearance will be necessary from DGTD or Department of Electronics.”

3 आयात-निर्यात नीति में उपर्युक्त संशोधन सार्वजनिक हित में किये गये हैं।

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO 42-ITC(PN)/85—88

New Delhi, the 16th October, 1985.

Subject : Import and Export Policy for April 1985—March 1988.

File No. IPC/3/7/85:—Attention is invited to the Import and Export Policy for April 1985—March 1988, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC(PN)/85—88 dated the 12th April, 1985 as amended.

2. The following amendments shall be deemed to have been made in the Policy at appropriate places indicated below:—

Sl. No.	Page No. of Import and Export Policy, 1985—88 (Volume I)	Reference	Amendment
1	2	3	4
1	38	Chapter VII Para 127(5)	This sub-para shall be substituted by the following:— “(5) The Oil & Natural Gas Commission, Oil

2. 39	Chapter VII Para 127(7)	The words “indigenous clearance from DGTD/ Deptt. of Electronics” appearing in seventh and eighth lines in this sub-para shall be amended as “clearance from the Empowered Committee on Indigenisation in the Oil Industry under the Ministry of Petroleum and Natural Gas.”
-------	-------------------------	--

3. The above amendments in the Import and Export Policy have been made in the public interest.

R. L. MISRA, Chief Controller
of Imports & Exports